

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2313
मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक)को उत्तरार्थ

अनाज भंडारण सुविधा के लिए समझौता

+2313. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण सुविधा स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों के साथ कोई समझौता किया है;
- (ख) यदि हां, तो इसमें शामिल सहकारी समितियों सहित इन समझौतों और प्रस्तावित अनाज भंडारण सुविधाओं के स्थानों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन समझौतों के अंतर्गत कुल कितनी भंडारण क्षमता की योजना बनाई गई है और इसे पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और
- (घ) इन अनाज भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदन प्रदान किया, जिसे एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि के अभिसरण के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि में प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) के स्तर पर गोदाम, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों, आदि जैसी विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण करना शामिल है।

पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके लिए संबंधित पैक्स और नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसिज़ (नैबकोंस) के बीच समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किए गए। 11 पैक्स के ब्यौरे सहित जिला/ राज्य के नाम और निर्मित गोदामों की क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पैक्स का नाम	जिला	राज्य	गोदाम की क्षमता (मीट्रिक टन)
1.	नेरीपंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	अमरावती	महाराष्ट्र	3,000

2.	बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	1,500
3.	दी चंद्रनगर ग्रूप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	अहमदाबाद	गुजरात	750
4.	घमुडवाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	श्री गंगानगर	राजस्थान	250
5.	बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी मर्यादित परसवाड़ा	बालाघाट	मध्य प्रदेश	500
6.	बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	देहरादून	उत्तराखंड	500
7.	सिलमराथुपट्टी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी	थेनी	तमिलनाडु	1,000
8.	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, गंभीराओपेट	करीम नगर	तेलंगाना	500
9.	2 नं. पब बोंगशार जी.पी.एस.एस लिमिटेड	कामरूप	असम	500
10.	प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, एकंबा	बीदर	कर्नाटक	1,000
11.	खिलपाड़ा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	गोमती	त्रिपुरा	250

पायलट परियोजना के तहत देश के 11 राज्यों में कुल 9,750 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है ।

पैक्स स्तर पर अभिसरित की जा रही भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध परिव्यय का उपयोग करके इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।
